छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक PROJ/330/2025-COMM. & INDUS. नवा रायपुर, दिनांक /06/2025

12 JUN 2025

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/गृह विभाग/वन एव जलवायु परिवर्तन विभाग/कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग/लोक निर्माण विभाग/खनिज साधन विभाग /खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग/परिवहन विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग/इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग/ खेल एवं युवा कल्याण विभाग/ विमानन विभाग/पर्यटन एवं संस्कृति विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, अटल नगर रायपुर।

2. उप सचिव (लॉजिस्टिक्स),
भारत सरकार,
उद्योग संवर्धन एवं आतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
नई दिल्ली।

3. आयुक्त,
आबकारी,
आबकारी भवन,रायपुर

4. महानिदेशक,
BISAGIN, गांधी नगर, गुजरात

5. संचालक,
CONCOR, रायपुर

6. संचालक,
संस्थागत वित्त, इन्द्रावती भवन,
अटल नगर, नवा रायपुर

7. संचालक,
तकनीकि शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर

8. संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर

9. संचालक,
उद्यानिकी संचालनालय, रायपुर

10 संचालक,
पुरातत्व, रायपुर

11. प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोंपज संघ,
नवा रायपुर

12 प्रबंध संचालक,
मंडी बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़

13. आयुक्त,
गृह निर्माण मण्डल, नवा रायपुर

14. प्रबंध संचालक,
पर्यटन मण्डल, रायपुर

15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
नवा रायपुर विकास,प्राधिकरण,नवा रायपुर

16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
रायपुर विकास प्राधिकरण
रायपुर

17. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ राज्य कौशल
विकास प्राधिकरण, रायपुर

18. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
चिप्स, स्टेट डाटा सेंटर के पास,
नवा रायपुर

19. नियंत्रक,
मापतौल, इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर

विषयः— प्रधानमंत्री गति—शक्ति परियोजना के अंतर्गत गठित **Empowered Grouped of Secretaries (EGOS)** की बैठक दिनांक 10.06.2025 की सूचना बाबत।

—00—

विषयातर्गत प्रधानमंत्री गति—शक्ति परियोजना के कियान्वयन की समीक्षा हेतु अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में

निरंतर.....

Empowered Group of **Secretaries** (**EGOS**) की दिनाक 10.06.2025 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
Magan Lal Pawar
Date: 13-06-2025
10:44:14

(एम.एल.पवार)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृ.क्रं. PROJ/330/2025-COMM. & INDUS. नवा रायपुर, दिनांक /06/2025

12 JUN 2025

प्रतिपिलपि:–

1. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2 निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालयए अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री प्रभात मलिक, संचालक एवं नोडल अधिकारी, पीएम गतिशक्ति उद्योग संचालनाय, उद्योग भवन, रायपुर।
5 प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, उद्योग भवन, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12/6/2025
अनुभाग अधिकारी,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

नवा रायपुर ,
दिनांक / /2025

कार्यवाही विवरण

विषय :- प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना अंतर्गत EGoS की 7वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

अपर मुख्य सचिव महोदया, छ. ग. की अध्यक्षता में दिनांक 10 जून 2025 को अपराह्न 4:00 बजे प्रतिकक्ष क्र. एस-3/12 मंत्रालय, अटल नगर रायपुर में प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना की समीक्षा हेतु EGoS (Empowered Group of Secretaries) की बैठक संपन्न हुई । चर्चा का सारांश निम्नानुसार है :-

- बैठक में प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना (PM Gati Shakti) का संछिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए ,राज्य की प्रगति पर समीक्षा की गई। योजना अंतर्गत बनाए गए Use cases जैसे औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि चिन्हांकन, PVTG बस्तियों के लिए स्वास्थ्य सुविधा और पहुँच मार्ग के समाधान जैसे उदाहरण प्रस्तुत किए गए ।
- विभिन्न विभागों द्वारा साझा किए गए mandatory layers और additional layers की स्थिति की समीक्षा की गई और पाया गया कि कई layers अभी SOP के अनुरूप नहीं हैं।

विभागों से अपेक्षित कार्यवाही :-

1. जल संसाधन विभाग (Water Resource Department): विभाग ने अवगत कराया कि उनके द्वारा विभिन्न data layers तैयार किए गए है जिसे वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (Department of Commerce & Industries) से साझा किया जावेगा ।

   (कार्यवाही - जल संसाधन विभाग)

2. लोक निर्माण विभाग (PWD): विभाग ने अवगत कराया कि 395 सड़कों का digitization किया जा चुका है, शेष 195 सड़कों के geo-referencing कार्य 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा ।

(कार्यवाही - लोक निर्माण विभाग)

3. नगरीय प्रशासन विभाग (Urban Administration Department): विभाग ने अवगत कराया कि geo-referenced property tax data का कार्य अगस्त अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा तथा शेष सभी mandatory एवं additional layer की जानकारी 30 जून तक साझा कर दी जावेगी। विभाग द्वारा City logistic plan के निर्माण पर कार्यवाही की जा रही है।

(कार्यवाही - नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

4. आवास एवं पर्यावरण विभाग (Housing & Environment Department): विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि State logistic plan व City logistic plan पर नगरीय प्रशासन विभाग के साथ चर्चा कर 6 माह में Action plan का निर्माण पूर्ण किया जावेगा ।
5. span>कार्यवाही- आवास एवं पर्यावरण विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)
6. सरकारी भवनों के geo-referencing हेतु CEO, CHiPS द्वारा अवगत कराया गया कि, चिप्स द्वारा mobile app विकसित कर रहा है जिससे सभी सरकारी भवनों के geo-referencing का कार्य किया जा सकेगा। App का निर्माण 7 दिवसों में पूर्ण हो जाएगा। mobile app का प्रयोग कर शासकीय भवनों के geo -referencing का कार्य 3 महीने में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए ।

(कार्यवाही - CHiPS एवं समस्त विभाग)

6. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (Panchayat & Rural Department): विभाग को village habitation data तीन माह में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया ।

(कार्यवाही - पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

7. महिला एवं बाल विकास विभाग (Women & Child development Department): विभाग द्वारा अवगत कराया कि, Child Care का डाटा पूर्व में केन्द्रीय मंत्रालय से साझा किया जा चुका है ,गतिशक्ति पोर्टल हेतु पुनः साझा करना कार्य की पुनरावृति है । उक्त तारतम्य में सभी विभागों से अनुरोध किया गया कि वे केंद्रीय मंत्रालयों को साझा किया गया data (यदि कोई है) CHiPS को प्रदान करें, जिससे उसका Integration CG Geo Portal में किया जा सके, क्योंकि BISAG-N द्वारा State Master Plan में data upload करने में 2–3 माह

का समय लगता है।

(कार्यवाही - समस्त विभाग)

8. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (Department of Food & Civil Supplies): विभाग ने EV charging Stations का विवरण साझा करने की सहमति दी। MD, CSPGCL ने भी उक्त डाटा तथा विभाग से सम्बंधित अन्य डाटा साझा करने की प्रतिबद्धता जताई ।

(कार्यवाही - खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, CSPGCL)

9. उद्योग संवर्धन और आतंरिक व्यापार विभाग (DPIIT), भारत सरकार ने अवगत कराया कि उन्होंने BISAG-N को Office Memorandum जारी किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के सभी data उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही– BISAG-N)

10. BISAG-N ने अवगत कराया कि उत्तराखंड और गुजरात के Use cases का compendium छत्तीसगढ़ के साथ साझा किया गया है। BISAG-N द्वारा इन use case से सम्बंधित अन्य जानकारी 15 दिवस में साझा करने की प्रतिबद्धता जताई।

(कार्यवाही – BISAG-N)

11. वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (Department of Forest & Climate Change): विभाग द्वारा अवगत कराया कि उनके पास एक dedicated GIS टीम है और अन्य विभाग उनके द्वारा निर्मित GIS data का उपयोग कर सकते है । साथ ही उन्होंने विभागीय नियमानुसार वन क्षेत्र के पास स्थित (10 किमी की दूरी पर) आरा मिलों के प्रतिस्थापन का Use case निर्माण हेतु प्रतिबद्धता जताई है ।

(कार्यवाही – वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)

- बैठक में अध्यक्ष महोदया से प्राप्त निर्देश निम्नानुसार हैं :-

1. सभी विभाग mandatory data layers (भू- अभिलेख, habitation, तथा शासकीय भवनों की जानकारी के अतिरिक्त) 30 जून 2025 तक साझा करें तथा additional layers की जानकारी साझा करने की समयावधि 15 दिवस के भीतर (दिनांक

25 जून 2025 तक) नोडल विभाग को अवगत कराएं। आगामी बैठक में की गयी कार्यवाही की जानकारी के साथ प्रस्तुत होने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही - समस्त विभाग)

2. सभी विभाग ₹50 करोड़ से अधिक की चल रही परियोजनाओं को 3 माह के भीतर गतिशक्ति प्लेटफॉर्म से integrate करने हेतु जानकारी साझा करें।

(कार्यवाही - समस्त विभाग)

3. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (Commerce & Industries Department) को निर्देशित किया गया कि वे योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से PFIC द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की सूची प्राप्त करें और उनमें से चयन कर PM GatiShakti Annual Action Plan के अंतर्गत upload हेतु चिन्हित करें।

(कार्यवाही - वाणिज्य एवं उद्योग विभाग)

4. सभी विभाग को न्यूनतम एक Use case का चयन कर 30 जून तक जानकारी नोडल विभाग से साझा करने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही - समस्त विभाग)

5. गतिशक्ति योजना हेतु समस्त विभाग नोडल अधिकारी की नियुक्ति 7 दिवस के भीतर करते हुए, पोर्टल के उपयोग हेतु User ID 15 दिवस के भीतर निर्मित करे तथा तकनीकी सहायता हेतु नोडल विभाग से ट्रैनिंग हेतु संपर्क करे।

(कार्यवाही - समस्त विभाग)

बैठक का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।

Digitally signed by
RAJAT KUMAR
Date: 12-06-2025
17:18:58

(रजत कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग